prosecution against M/s. I.T.C. Limited in pursuance of the order of Director General of Inspection dated the 10th April, 1986 for the 'Brand law' violation in respect of their famous cigarette 'NOW';

(c) if so, what steps have so far been taken by Government in this direction; and

(d) if the answer to part (c) above be in the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) to (c) The case relating to 'NOW' brand cigarettes has been decided by the Collector of Central Excise, Bangalore on 18-7-1988. The order of the Director-General of Inspection, dated the 10th April, 1986 does not relate to 'NOW' brand cigarettes. The Collector of Central Excise, Bangalore has already sanctioned prosecution in this case on 17-4-1989.

मध्य प्रदेश में अग्रिम सूचना केन्द्रों का स्थापित किया जाना

1134. **श्री अजीत जोगी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ के संबंध में अग्रिम सूचना देने के लिए मध्य प्रदेश में इस समय कितने अग्रिम चेतावनी केन्द्र कार्यरत हैं ;

(ख) क्या ऐसे कुछ और चेतावनी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दो ।

(ख) नर्मदा नदी पर मांडला में एक ।

(ग) जी नहीं ।

धागों की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश में विद्युत चालित करघा और हथकरघा उद्योगों की समस्याएं

1135. श्री अजीत जोगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धागे की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि तथा नई वस्त्र नीति के कारण मध्य प्रदेश के विद्युतचालित करघा और हथकरघा उद्योग कठिन वित्तीय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) वर्तमान में इन दोनों सेक्टरों का औसत उत्पादन कितना है और उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कारणों से उत्पादन में क्या-क्या परिवर्तन या कमी आने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जहां एक ओर यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है, वहीं विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में उत्पादन में भी वृद्धि हुई हैं । विभिन्न क्षेत्रों पर वस्त्र नीति की समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक समिति को पहले से ही नियुक्त किया हैं । सरकार जहां कहीं आवश्यक होता है वहां सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए स्थिति की नियमित रूप से मानीटरिंग करती हैं । सरकार ने वर्ष 1987 से स्टेपल रुई का निर्यात स्थगित कर दिया था । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूती यार्न के निर्यात का सूती यार्न की घरेलू उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सूती यार्न, सूती फब्रिक्स और मैडअप्स के निर्यात पर अग्रिम लाइसेंस के आधार पर रुई के आयात की अनुमति दी गई हैं । 60 काउंटों तक के हैंक यार्न का निर्यात स्थगित कर दिया गया है । सरकार यार्न के उत्पादन के लिए अपेक्षित रुई की उपलब्धता आदि के बारे में स्थिति की कड़ी निगरानी भी रखती है ।